



# ਹਾਥਪੁਰ ਮੈਂ ਮੈਨਯੁਫ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡੇ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ

108 बच्चों के गाए गीत 'पधारो म्हारे देस' सुन प्रवासी गदगद, राइजिंग राजस्थान के मंच पर प्रवासियों ने साझा किए अनुभव



इंडिया न्यूज

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल

## राजस्थान वीरों की भूमि

प्रवासी उद्योगपति एन.सेटिया गुप्त  
ऑफ कंपनीज (यूके) के फाउंडर एवं  
चेयरमैन निर्मल कुमार सेटिया ने अपने  
विचार व्यक्त करते हुए कहा कि  
राजस्थान वीरों की भूमि है और इसे  
साहस और वीरता के लिए जाना जाता  
है। उन्होंने कहा कि सफल होने के  
साथ ही हम सभी को एकता और  
मानवता को भी अपनाना चाहिए।

# सऊदी अरब ने खनन और पेट्रो सेक्टर में दिखाई रुचि

संभावनाओं पर राइजिंग राजस्थान में  
अधिकारियों के साथ हुई चर्चा

जयपुर। सऊदी अरब के उप मंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में खनिज और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी.एविकांत ने बताया कि माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सऊदी अरब के उप मंत्री शेख मजीद फलाह और शेख अब्दुल्ला के साथ राज्य में इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। टी.एविकांत ने बताया कि अतिरिक्त निदेशक माइंस बी.एस.सोढा ने सउदी अरब दल के सदस्यों को विस्तार से प्रदेश में उपलब्ध मिनरल्स, एक्सल्यूरेशन और निकट भविष्य में होने वाले मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने

बताया कि राजस्थान में डेकोरेटिव स्टोन के साथ ही क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के भंडार हैं और चरणबद्ध तरीके से इनके ब्लॉक्स तैयार कर नीलाम किए जारहे हैं।

अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा ने राजस्थान रिफाइनरी और उसके आसपास के क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल जोन विकसित होने की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश में उपलब्ध क्रूड ऑयल और गैस के भंडारों की खोज और दोहन के संबंध में अवगत करवाया।

सऊदी अरब के उप मंत्री शेख अब्दुल मजीद फलाह और मुख्य कायुकारी अधिकारी शेख अब्दुल्ला ने खनिज के साथ ही रिफाइनरी के आसपास के क्षेत्र में विकसित हो रहे पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक निवेश में रुचि दियाई।

वहीं, कॉन्कलेव की शुरुआत में कर्नल

राज्यवद्धन सिंह राठीड ने कहा कि हमने निवेशकों के लिए लालफीताशाही खत्म कर रेड कारपेट बिछाने का काम किया है। हम 21 नई पॉलिसी लेकर आए हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से कहा कि आपका आपके घर में स्वागत है और जब आप अपने घर पर आते हैं तो वह एक त्योहार होता है। आपने राइजिंग राजस्थान समिट को एक त्योहार के रूप में मनाया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राइजिंग राजस्थान समिट बेशक तीन दिन का है, लेकिन इसका कभी अंत नहीं होगा। यह लगातार चलता रहेगा।

अर्थव्यवस्था है।



# एशिया फैशन ट्रू में दिखेगा फैशन का जलवा

13 से 16 दिसंबर तक  
मॉडल करेंगी रैप वॉक

इंडिया न्यूज़



उत्तरगढ़ और फेमिना फाइनलिस्ट 2022 ऐश्वर्या नौटीयाल भी मौजूद रहीं। उन्होंने अपने प्रतिभाशाली मॉडल्स और डिजाइनर की टीम के साथ एक शानदार प्रस्तुति दी।

आयोजन समिति के सदस्य गुरुप्रीत सिंह ने बताया कि इस चार दिवसीय फैशन शो में फैशन के जीवंत संग्रहों, इनोवेटिव डिजाइन और डायामिक फैशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें पारंपरिक परिधानों से लेकर अत्याधुनिक ऐलियों तक रचनात्मक और शिल्प कौशल का संगम होगा। आयोजन समिति के सदस्य निखिल भटनागर और प्रीति सचदेवा भी इ

**महिला नेता का युवती  
ने बनाया अश्लौल  
वीडियो, डिलीट करने  
के मार्गे 10 लाख**

जयपुर। शहर में एक महिला नेता  
अश्वील वीडियो बनाकर लैंकमेल करने  
मामला सामने आया है। आरोप है  
उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने ही घर में हि  
फैमरे लगा कर महिला नेता का अश्वी  
ल वीडियो बनाया और वायरल करने  
धमकी देकर डिलीट करने के बदले  
लाख रुपये की मांग की। इस मामले  
महिला ने कार्यकर्ता सहित 2 लोगों  
खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। म  
दूसरी थाना पुलिस मामले की जांच  
रही है। पुलिस ने बताया कि पीडित  
रिपोर्ट में बताया कि उसके घर पर 3 र  
से एक युवक रहता था और उसका सो  
भीडिया अकाउंट संभाल रहा था। मंगेत  
मिलने के दोस्रान आरोपी ने उनके प्राइ  
वीडियो बना लिए। युवक दोस्त के र  
शुक्रवार को पीडिता के घर आया 3  
मोबाइल में अश्वील वीडियो दिखाते हुए  
वायरल करने की धमकी दी।

अब ऑनलाइन अपलोड होंगी भर्ती  
परीक्षाओं की ओएमआर शीट, कर्मचारी  
चयन बोर्ड का फैसला

इंडिया न्यूज

हेडन  
क्षील  
की  
10  
ले में  
ि के  
मोती  
कर  
ा ने  
साल  
शल  
र से  
इवेट  
साथ  
और  
उसे

जयपुर। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब अध्यर्थियों की ओएमआर शीट को भी ऑनलाइन अपलोड करने का फैसला किया है। बोर्ड की ओर से 16 से 20 नवंबर के बीच हुई कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट को अपलोड करने के साथ इसकी शुरूआत की जाएगी। अगर यह प्रक्रिया सफल रहती है तो आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में इसे लागू किया जाएगा। प्रदेश में होने वाली भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट को मेरिट बेस करने के बाद अब बोर्ड ने ओएमआर शीट को भी ऑनलाइन अपलोड करने का निर्णय किया है। अध्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के जरिए परीक्षा में सकेंगे और इन्हें डाउनलोड भी कर सकेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में कई अध्यर्थियों को ओएमआर शीट को लेकर आपत्ति रहती है।

कई अध्यर्थियों को ओएमआर शीट बदले जाने की आशंका रहती है। अब इसमें पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ओएमआर शीट को ऑनलाइन अपलोड करने की प्लानिंग की जा रही है। पहला प्रयोग जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट को अपलोड करने के साथ किया जाएगा। यह भर्ती परीक्षा 16 से 20 नवंबर के बीच आयोजित कराई गई थी। इस भर्ती परीक्षा की ओएमआर शीट अध्यर्थी 10 जनवरी तक ऑनलाइन देख सकेंगे।







जयपुर, बुधवार, 11 दिसंबर 2024

# तैयरियों में तो आप आगे



अरविन्द मोहन

वरिष्ठ संपादक

चुनावी सुगबुगाहट तो बिहार में भी कब से सुरू है जहाँ अगले साल अक्टूबर से पहले विधान सभा चुनाव होना है और इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे तेज हलचल राजधानी दिल्ली में है जहाँ कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है। इससे भी बड़ी जात ये है कि वहाँ जिन दो पार्टियों के बीच चुनावी मुकाबला है अर्थात् भाजपा और आप, वे साल भर और 24 घंटे चुनावी मूँड में रहने वाली पार्टियाँ हैं। इन दोनों पार्टियों ने लगातार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसी का परिणाम है कि चुनाव घोषित नहीं हुए और लगभग चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। उम्मीदवारों के नाम घोषित होने लग गए हैं और

वाली पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों ने लगातार एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसी का परिणाम है कि चुनाव घोषित नहीं हुए और लगभग चुनाव प्रचार शुरू हो गया है उम्मीदवारों के नाम घोषित होने लग गए हैं।

कार्यक्रमों की झड़ी लग गई है कहना न होगा कि इस काम में भाजपा पूरे पांच साल से लगी हुई है और उसने आप की राज्य सरकार को गिराना है और उसके नाक में दम करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई बार उसकी कोशिशें संसदीय मर्यादाओं के उलट भी हुई हैं और सब किसी को ये लगता है कि ये कदम है आप के नेताओं को परेशान करने के लिए उठाए जा रहे हैं तो किसी को भी यह समझने में दिक्कत नहीं होती है न कि किस तरह से आप ने भाजपा को पराजित किया है। भाजपा के लिए यह ज्यादा परेशानी की बात है क्योंकि नरेन्द्र मोदी का डंका पूरे देश में बजता है लेकिन बार बार दिल्ली मैं उनको पराजय खेलनी पड़ती है। उससे पहले भी दिल्ली में लगातार पंद्रह साल कॉर्गेस की सरकार रही है। इस तरह से भाजपा बीते पच्चीस वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रही है।

और आप तो आपने उसे स्थानीय निकाय चुनावों में भी बुरी तरह पराजित कर दिया है। इस पराजय के साथ ही यह सच्चाई भी भाजपा को दिखाई देती है कि लोक सभा चुनावों में उसे किसी कि स्म का दबाव या चुनौती नहीं होती है। इस बार भी भाजपा ने बहुत आसानी से दिल्ली का चुनाव जीता जबकि आप ने कॉर्गेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस हिसाब से इस बार के चुनाव ज्यात दिलचस्प और करीबी हैं। दिलचस्प की खास बजह ये है कि इस बार आप का लगभग पूरा नेतृत्व किसी न किसी तरह के गंभीर आरोप से घिरा हुआ है। खुद अरविन्द केजरीवाल, उस पार्टी के नम्बर दो माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और लगभग पूरी पुरानी कैबिनेट दागदार हुआ है। यह जरूर है कि प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग/दुरुपयोग करने के बावजूद केंद्र सरकार आप के नेताओं के खिलाफ कोई खास सबूत या मुकदमा खड़ा नहीं कर पाई है। सभलाग जमानत पर छूटे हैं और अर्थ भी मुकदमे चल रहा है। इनका कहोगा यह भविष्यवाणी करना तो मुश्किल है लेकिन इतना करने में कोई हर्ज नहीं है कि आप के ज्यादातर बड़े नेताओं का दामन दागदार हो चुका है प्रश्नाचार खत्म करने के जिस बुनियादी दावे के साथ उन्होंने राजनीति शुरू की थी वह खत्म हो गई है। सदीका का नाम लेना भी अब उनके लिए उल्टा पड़ता है। उनके नेताओं के बारे में भाजपा सरकार गिराने में सफल हुई हो ना हुई हो लेकिन उसने आप के नेताओं की साथ जरूर गिराई है। और इसी का परिणाम है की आज अरविंद

राज्यपाल को भी बार बार अदालतों से फटकार मिल रही है। जो कदम वो उठाते हैं उसे कानूनी रूप से गलत बताया जाता है। खुद वे अदालतों से छुपते फिर रहे हैं क्योंकि जो बयान वे दे रहे हैं उसका छुट अदालतें जानती है। आप चुनाव के मामले में हैं बीजेपी से कमज़ोर नहीं है क्योंकि शासन का उसका रिकार्ड बहुत बढ़िया हो न हो भाजपा ही राज्यों से बेहतर है। भाजपा इसान जहाँ जहाँ है वहाँ बिजली पानी से लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है। इन सब मामलों में, शिक्षा में जो स्थिति है दिल्ली की है वह की स्थिति यूपी हरियाणा से बेहतर है। दिल्ली काफी कुछ लुटाके भी, लोगों में बैंट के भी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बेहतर स्थिति में है। शिक्षा का मामला हो स्वास्थ्य का, वृद्धावस्था पेंशन का मामला हो, दूसरी सहायियों का मामला हूँ दिल्ली अभी भी देश के बाकी राज्यों से बेहतर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है वहाँ भी बिजली मँगी है। मुफ्त बिजली वाली बात तो ही नहीं। वहाँ की सड़कों की हालत बदतर है। वहाँ के स्कूल किसी भी तरह से दिल्ली के स्कूलों से टक्कर नहीं ले सकते। शासन का यह रिकॉर्ड आप को भाजपा के मुकाबले मजबूत

लालू जैसे नेता भी नहीं है अब साथ में, राहुल अब हिम्मत तो करें बैसाखी छोड़ने की



अजीत मेंदोला

वरिष्ठ पत्रकार

नहीं दिल्ली। जिसका डर था, लगता है वही होने जा रहा है। कांग्रेस से उसके अपने धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इंडिया गढ़वंशन में शामिल दल एक एक कर उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। सपा, टीएमसी तक तो बात ठीक थी। लेकिन लालू यादव और शरद पवार की पार्टी भी अपना रुख बदलने लगे तो समझो राहुल गांधी के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि टारगेट वही है। राहुल अगर समझे तो बड़ा मौका भी है। अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत जुटाएं बिना बैशाखियों के खड़ा होने की कोशिश कर कर तो देखें। ऊरंत तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। लेकिन कोशिश करते करते क्या पता बात बन जाए। लेकिन इसके लिए उहें बिना मेहनत के सत्ता के लालची सलाहकारों से मुक्ति पानी होनी चाही तो सलाहकार हैं जो अपनी दुकान बचाने के लिए झूठा जय करा लगा पार्टी को ढुब्बने में लगे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस को ढुब्बने वाले गैर नहीं अपने ही हैं। पै

लेकिन लालू यादव और शरद पंवार की पार्टी भी अपना रुख बदलने लगे तो समझो राहुल गांधी के लिए कुछ भी ठीक नहीं है। क्योंकि टारगेट वही हैं। राहुल अगर समझो तो बड़ा मौका भी है। अपने पैरों पर खड़ा होने की हिम्मत जुटाएं। बिना बैशाखियों के खड़ा होने की कोशिश कर के तो देखो। तुरंत तो खड़ा नहीं हुआ जाएगा। लेकिन कोशिश करते करते क्या पता बात बन जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें बिना मेहनत के सत्ता के लालची सलाहकारों से मुक्ति पानी होगी। ये वो सलाहकार हैं

वी नरसिंह राव ने गठबन्धन की राजनीति का जो प्रयोग किया वह कांग्रेस के लिए कुछ समय तक के इलाई तो ठीक था। कुछ राज्यों तक भी सीमित रहता तो चल जाता। लेकिन सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभालने के बाद कोई अंकलन ही नहीं किया था उन्हें करने नहीं दिया गया। सत्ता के लालच में 2004 में कांग्रेस ने ऐसा कुनबा जोड़ा जो उनके लिए भस्मासुर सांवित हुआ। जन क्षेत्रीय दलों के दम पर कांग्रेस ने सरकार बनाई उन्होंने अपने को राज्यों में मजबूत किया लेकिन कांग्रेस को ढुबो दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कई राज्य हैं जहां कांग्रेस हाशिए पर चली गई। 2009 में वरिष्ठ नेता जनादेव द्विवेदी ने जरूर सलाह दी थी कि कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा हो खुद के दम पर बहुमत लाना चाहिए। उनकी यह सलाह उन पर ही भारी पड़ गई। राहुल के युवा चौकड़ी उन्हें भागाने में जुट गई। और किनारे लगाने में सफल भी रहे। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता था कि इस देश में उनके अलावा कोई और राज कर ही नहीं सकता। थर्म और जाति में बढ़े इस देश में हिंदू समर्थक बीजपी की सत्ता में आ ही नहीं सकती। कांग्रेस को बीजेपी तो दिखी लेकिन उसके पीछे जो संघ दशकों से काम कर रहा था उसका अंकलन ही नहीं किया। बीजेपी को रोकने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति अपना उन क्षेत्रीय दलों को साथ लेने में जुट गई जो राज्यों में जाति और मुस्लिम

इंडिया गढ़बंधन की तरफ से लड़ने निकल पड़े। 2024 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत से चूक गई, लेकिन सहयोगियों के दम पर उसने बहुमत हासिल किया। राहुल इसे ही जीत मान विषयक के नेता बन गए। लेकिन 6 माह में ही महाराष्ट्र और हरियाणा की हार ने उनके लिए संकट खड़ा कर दिया।

अभी तक जिन्होंने कभी आंख नहीं दिखाई थी वह भी आंख दिखाने लगे। शजद नेता लालू यादव ने राहुल का नेतृत्व अस्वीकार कर टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी को नेता मान लिया। टीएमसी तो शुरू से ही राहुल के नेतृत्व के खिलाफ थी। वामदल भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है। शरद पंवार की पार्टी भी ममता को नेता मानने को तैयार है। सपा कही चुकी है। आम आदमी पार्टी को एतराज नहीं है। ले दे कर डीएमके के है वह भी पाला बदल सकती है। अगर आने वाले दिनों में विषयकी कमान ममता बनर्जी संभालती हैं तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन वहीं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस के लिए मौका भी होगा। राहुल अपने मौजूदा सलाहकारों से मुक्ति पा पुराने अनुभवी चेहरों को संगठन में वापस ला अपने दम पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं तो पार्टी हित में होगा। क्योंकि जो दल अभी सवाल उठा रहे हैं उनसे कांग्रेस को बहुत फायदा है नहीं। कांग्रेस अकेले लड़ी तो क्या पता स्थिति बदल जाए। लेकिन इसके लिए हिम्मत और कड़े फैसले राहुल गांधी को खुद ही लेने होंगे।

## लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है भ्रष्टाचार



ॐ जपातीर्थ सिंह

भ्रष्टचार विरोधी दिवस प्रतिवर्ष ९ दिसम्बर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ३१ अक्टूबर, २००३ को संयुक्त राष्ट्र ने एक भ्रष्टचार निरोधक समझौता पारित किया था और तभी से यह दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में एक समृद्ध, ईमानदार, पारदर्शी, नैतिक एवं मूल्यांधारित समाज को बनाए रखने के लिए भ्रष्टचार को खस्त करना इस दिन का मुख्य देहश्य है। तेजी से वाप प्रसार रहा भ्रष्टचार किसी एक समाज, प्रांत

पूरे विश्व में एक समृद्ध, ईमानदार, पारदर्शी, नैतिक एवं मूल्याधारित व्यवस्था को दूषित किया है, इसे रोकने के लिये प्रतीक  
या देश की समस्या नहीं है। इसने हर व्यवस्था को दूषित किया है, इसे रोकने के लिये प्रतीक्षा नहीं प्रक्रिया आवश्यक है। सत्ता एवं स्वार्थ ने भ्रष्टाचारमुक्ति को पूर्णता देने में उदासीनता दिखाई है। भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटना है जो सभी देशों को प्रभावित करती है। भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर करता है, आर्थिक विकास को धीमा करता है और सरकारी अस्थिरता में योगदान देता है हमारा विश्व अनेक चुनौतियों, त्रासदियों, असमानताओं और अन्यायों का सामना कर रहा है, जिनमें से अनेक भ्रष्टाचार से जुड़ी हैं। विश्व में 1.9 अरब युवा हैं, तथा भ्रष्टाचार से लड़ना बैशिक जनसंख्या के लगभग एक-चौथाई भाग के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। देशों के विकास को केवल राजनीतिज्ञों के भरोसे छोड़ देने का यह नहीं है। जबकि हमारे साथ या बाद में आजाद हुए देशों की प्राप्ति अनेक क्षेत्रों में हमसे अधिक बेहतर है, बाबूजूद इसके कि संसाधनों व दिमागों की हमारे पास कमी नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं, जो न विधायक हैं, न सांसद, न मंत्री, पर वे तटस्थ व न्यायेचित दृष्टिकोणों से अपनी प्रबुद्धता व चरित्र के बल पर राष्ट्र के व्यापक हित में अपनी राय व्यक्त करते हैं। आवश्यकता भी है कि ऐसे साफ दिमागी, साफ गिरेबान के लोगों का समूह आगे आए और इन रंग चढ़े हुए राजनीतिज्ञों एवं भ्रष्टाचार में आकर डूँगे नौकरशाहों एवं सत्ताधरियों के लिए आईना बनें। भ्रष्टाचार चुनावी प्रक्रियाओं को विकृत करके, कानून के शासन व विकृत करके और नौकरशाही के दलदल को पैदा करके लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव पर हमला करता है जिसके अस्तित्व का एकमात्र कारण रिश्वत मांगना है। आर्थिक विकास अवरुद्ध है, व्यांकों प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होतोसाहित है और देश के भीतर छोड़े व्यवसायों को अक्सर भ्रष्टाचार के कारण आवश्यक; स्टार्ट-अप लागत को पूरा करना असंभव लगता है। 31 अक्टूबर 2003 को, महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया और

माज को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार को खत्म करना इस दिन का मुख्य ही प्रक्रिया आवश्यक है। सत्ता एवं स्वर्ध ने भ्रष्टाचारमुक्ति को पूर्णता देने के लिए अनुरोध किया कि वे कन्वेशन के सदस्य देशों के सम्मेलन ( संकल्प 58/4 ) के सचिवालय के रूप में संयुक्त राष्ट्र ड्रास और अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी) को नामित करें। तब से, 190 दलों ने कन्वेशन के भ्रष्टाचार विरोधी दायित्वों के लिए प्रतिबद्धता जर्ताई है, जो सुशासन, जवाबदेही और राजनीतिक प्रतिबद्धता के महत्व की लगभग सार्वभौमिक मान्यता को दर्शाता है। भ्रष्टाचार दुनिया के सभी हिस्सों में व्याप है, यह किसी भी देश के आर्थिक विकास को धीमा करता है, तभी इस विकराल होती समस्या पर नियंत्रण पाने के लिये संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने करने का निश्चय किया। इस वर्ष इस दिवस की थीम है : भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना कल की ईमानदारी को आकार देना ; यह थीम भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में युवाओं को शामिल करने पर केंद्रित है, जो युवाओं को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाइ का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर हम सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने हुए दुनिया के कठिपय राष्ट्रों ने ईमानदार साशन व्यवस्था देने का उदाहरण प्रस्तुत किया है, अब इसकी व्यावहारिकता पर जोर देने का समय भी आ चुका है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सभी के साथ-साथ व्यावहारिक कदम उठाने की सख्ताकर से अपेक्षा है। आजादी का अमृत महोत्सव माना चुके देश में भ्रष्ट कार्य संस्कृति ने देश के विकास को अवरुद्ध किया। आजादी के बाद से अब तक देश में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का हिसाब जोड़ा जाए तो देश में व्यापक स्तर पर विकास हो सकता था।

दूषित राजनीतिक व्यवस्था, कमजोर विषय और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत ने पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार के कुएं में धकेलने का काम किया। देखना यह है कि क्या वास्तव में हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकेगा ? यह प्रश्न आज देश के हर नागरिक के दिमाग में बार-बार उठ रहा है। वर्तमान सरकार

उद्देश्य है। तेजी से पांच पसार रहा भ्रष्टाचार किसी एक समाज, प्रांत में उदासीनता दिखाई है। भ्रष्टाचार एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक की नीति और नीयत देश को भ्रष्टाचार मुक बनाने की है, लेकिन उसका असर दिखाना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल जनता के सेवक बनने की बजाय स्वामी बन बैठे। विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार की सीमा को मापने का एक तरीका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, जिसे टांसपेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतीर्वश प्रकाशित किया जाता है, जो नीति निर्माताओं और संगठनों को भ्रष्टाचार रूपी समस्याओं को पहचानने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए बेहतर रणनीति बनाने में मदद करता है। ग्लोबल क्रशन परसेशन इंडेक्स में भारत की स्थिति चिंताजनक रही है। 2023 में भारत 40 अंकों के साथ 180 देशों में 93वें स्थान पर था। यह स्कोर दर्शाता है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारत को अभी भी लम्बा रास्ता तय करना है।

भारत ने भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कई भ्रष्टाचार विरोधी कानून और नीतियां लागू की हैं। इनका उद्देश्य जवाबदेही को मजबूत करना और

नैतिक शासन सुनिश्चित करना है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 भ्रष्टाचार को परिभासित करता है और लोक सेवकों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड निर्धारित करता है। इसे 2018 में संशोधित किया गया और रिश्वत देने वालों के लिए दंड को शामिल करने के लिए पीसीए के द्वारा विस्तार किया गया।

भारतीय न्याय सहिता, 2023 इस अधिनियम ने भारतीय दंड सहिता, 1860 का स्थान लिया। इसने भ्रष्टाचार से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का आधिकारिकरण और सुधार किया ताकि रिश्वतखोरी के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापक समस्या है। भारत में इसने कहर ढाया है। इसके खिलाफ लड़ाई केवल किए जाने की नहीं, 1 अरब 25 करोड़ जनता के हितों की लड़ाई है जिसे हर व्यक्ति को लड़ाना होगा। वही हारा जो लड़ा नहीं- अगर हम नहीं लड़े तो भ्रष्टाचार की आग हर घर को स्वाहा कर देगी। हर गण्ड के सामने चाहे वह कितना ही

देश की समस्या नहीं है। इसने हर और आर्थिक घटना है समझ हो, विकसित हो, कोई न कोई चुनौती रहती ही है। चुनौतियों का सामना करना ही किसी राष्ट्र की जीवंतता का परिचायक है। चुनौती नहीं होतो राष्ट्र सजाएगा, नेतृत्व निष्क्रिय हो जाएगा। चुनौतियां अगर हमारी नियति हैं, तो उसे स्वीकारना और मुकाबला करना हमें सीखना ही होगा और इसके लिए हर व्यक्ति को अन्ना हजारे बना होगा। और साथ ही जन-जागरिति के बिना प्रश्नाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। अजग आवश्यकता केवल एक होने की ही नहीं है, आवश्यकता केवल चुनौतियों को समझने की ही नहीं है, आवश्यकता है कि हमारा मनोबल फूँ हो, चुनौतियों का सामना करने के लिए हम ईमानदार हों और अपने स्वार्थ को नहीं परार्थ और राष्ट्रहित को अधिमान दें। अन्यथा कमज़ोर और धघल राष्ट्र को खतरे सदैव धेरे रहेंगे।

(लेखक गवर्नरेंट कॉलेज नागरणगढ़ के राजनीतिक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)











